एप्पेलेट सिविल

*Mehar Singh,*मुख्य न्यायमूर्ति और *Bal Raj Tuli, न्यायमूर्ति* के समक्ष**,**

राम सरूप ई. टी. सी.,-अपीलार्थी

बनाम

पूरन ई. टी. सी.,-उत्तरदाता।

आर एस ए। नं. 1960 का 117.

30 अप्रैल, 1970।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5)-आदेश 21 नियम 35 (2)-कब्जा करने के लिए डिक्री समय के अंतराल से अप्रवर्तनीय होने के लिए-ऐसी डिक्री-चाहे वह मिट गई हो-डिक्री के पारित होने के बाद डिक्री धारक द्वारा अदालत से बाहर कब्जा प्राप्त करना-चाहे वह डिक्री के संतुष्टि के बराबर हो-उसके बाद डिक्री धारक को बेदखल करना-कार्रवाई का नया कारण-चाहे दूसरे मुकदमे के लिए उपार्जित हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कब्जा के लिए कोई डिक्री समय के अंत तक अप्रवर्तनीय हो जाती है, तो इसका केवल यह अर्थ है कि यदि कोई आवेदन किया जाता है तो निष्पादन न्यायालय डिक्री धारक को डिक्री के अनुसार कब्जा प्राप्त करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। लेकिन यह उस डिक्री को मिटाता नहीं है जो वैध रूप से पारित की गई है।

अभिनिर्धारित किया गया कि डिक्री धारक द्वारा उसके अनुसार डिक्री पारित किए जाने के बाद न्यायालय से बाहर कब्जा प्राप्त करना कब्जे के लिए डिक्री की संतुष्टि के बराबर है। यदि डिक्री धारक को उसके बाद बेदखल कर दिया जाता है, तो उसे अपने बेदखल होने के आधार पर दूसरा मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण मिलता है, बशर्ते कि मुकदमा उसके बेदखल होने की तारीख से सीमा के भीतर हो। वादी के नाम के समर्थन में पहले की डिक्री पर भरोसा किया जा सकता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह द्वारा 23 जनवरी, 1970 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक खंड पीठ को भेजा गया मामला। अंततः इस मामले का निर्णय माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर सिंह और माननीय न्यायमूर्ति श्री बाल राज तुली ने 30 अप्रैल, 1970 को किया।

रोहतक के जिला न्यायाधीश श्री हंस राज की अदालत के 18 अक्टूबर, 1959 के डिक्री से नियमित दूसरी अपील, जिसमें वादी के वाद को खारिज करते हुए सोनीपत के प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश श्री एस. एस. रायखे की तारीख 6 जून, 1959 की पुष्टि की गई थी।

निर्णय

B. R. TULI,न्यायमूर्ति--- यह अपील मेरे लॉर्ड द चीफ जस्टिस के समक्ष पहली बार सुनवाई के लिए आई थी और उनके द्वारा 23 जनवरी, 1970 के आदेश द्वारा निर्णय के लिए एक खंड पीठ को भेजी गई थी। इस तरह यह अपील हमारे सामने सुनवाई के लिए आई।

(2) मामले के इन तथ्यों को संदर्भ के क्रम में विस्तार से दिया गया है, लेकिन इसमें शामिल कानून के बिंदु को तय करने के लिए उन्हें फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है। तथ्य यह है कि वर्तमान वादी-अपीलार्थियों के पूर्ववर्तियों ने 20 अप्रैल, 1905 को कैथल, प्रतिवादी 4 और अन्य प्रतिवादियों के पूर्ववर्तियों के खिलाफ, जो अपील के सभी प्रतिवादी हैं, श्रीमती द्वारा छोड़ी गई पूरी भूमि के कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर

किया। दिलसुख की विधवा जिवानी, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले विधवा की संपत्ति के रूप में अपने जीवन के लिए संपत्ति धारण की थी। भूमि का माप 224 बीघा 5 बिस्वास था। उस मुकदमे के वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि वे दिलसुख और श्रीमती के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। जीवनी और वे पूरी भूमि के उत्तराधिकारी होने के हकदार थे। यहाँ यह कहा जा सकता है कि दलों के सामान्य पूर्वजों की तीन शाखाएँ थीं। वादी और उनके पूर्ववर्ती एक शाखा के थे जबकि प्रतिवादी और उनके पूर्ववर्ती दूसरी शाखा के थे। दिलसुख तीसरी शाखा के थे और बिना किसी समस्या के उनकी मृत्यु हो गई थी। 1900-1901 में तैयार किए गए राजस्व अभिलेखों में श्रीमती. जिवानी को दिलसुख की विधवा के रूप में उक्त भूमि के कब्जे में होने के रूप में वर्णित किया गया था और उनके द्वारा आयोजित भूमि एक अधिभोग किरायेदारी थी। उनकी मृत्यु 1904 में हुई और वर्ष 1904-1905 की जमाबंदी, प्रदर्शनी पी. 3, से पता चलता है कि उनकी मृत्यु पर भूमि को शामलत तुला पांडु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, दूसरे शब्दों में, गाँव में तुला पांडु के अधिकारधारकों की आम भूमि के रूप में। इस तुला पांडु में केवल 1905 के मुकदमे के वादी और प्रतिवादी शामिल थे। उस तुला में कोई अन्य सह-भागीदार नहीं था। उत्परिवर्तन में प्रवेश, जिसे बाद में जामबंदी में शामिल किया गया था, यह था कि थुला पांडु के अधिकारधारकों के खेवट में उनके हिस्से के अनुसार इस आम भूमि में हिस्सेदारी थी (hasab rasad khewat). इस प्रविष्टि को वाद में चुनौती दी गई थी क्योंकि वादी ने तब दावा किया था कि वे दिलसुख के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, लेकिन वाद की सुनवाई में उन्होंने संपत्ति के आधे हिस्से पर अपना दावा छोड़ दिया और केवल उस संपत्ति के आधे हिस्से के कब्जे का दावा किया, संभवतः इस आधार पर कि वादी और प्रतिवादी दिलसुख और उनकी विधवा श्रीमती द्वारा छोड़ी गई भूमि के उत्तराधिकारी होने के समान रूप से हकदार थे। जिवानी। विद्वत अधीनस्थ न्यायाधीश ने दिलसुख की विधवा श्रीमती द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के आधे हिस्से के संबंध में प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में एक आदेश पारित किया। जिवानी, 17 जुलाई, 1905 को। उस फरमान के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई और इस प्रकार यह अंतिम हो गया। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि इस डिक्री को वादी-डिक्री-धारकों द्वारा न्यायालय के माध्यम से कभी निष्पादित नहीं किया गया था, लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि 1909 में, वादी ने उक्त डिक्री के अनुसार अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया था। 1905 में मुकदमा दायर करने से पहले, वादी ने आरोप लगाया कि उनके पास पहले से ही 89 बीघा, 18 बिस्वास और 7 बिस्वासियों की जमीन थी। जमाबंदी हसब रसद खेवट में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार शेष 134 बीघा, 12 बिस्वास, 6 बिस्वासियों की भूमि प्रतिवादियों के कब्जे में थी। वर्तमान वादी और उनके पूर्ववर्तियों का उस भूमि पर कब्जा जारी रहा जो जुलाई, 1954 तक उनके हिस्से से अधिक थी, जब उनके गाँव में जोतों के समेकन की कार्यवाही शुरू हुई। पुनर्विभाजन में, समेकन अधिकारी ने वादी द्वारा विरोध के बावजूद, वादी और प्रतिवादियों को जमाबंदी हसद रसद खेवट में प्रविष्टि के अनुसार भूमि आवंटित की, न कि उस डिक्री के अनुसार जो 1905 में पारित की गई थी और जो अंतर-पक्ष होने के कारण उन पर बाध्यकारी थी। समेकन पर वादी और प्रतिवादियों के बीच विभाज्य होल्डिंग का कुल क्षेत्र 286 कनाल 8 मार्लास था। इस क्षेत्र में से, 62 कनाल 8 मरला को तुला पांडु के लिए संयुक्त छोड़ दिया गया था और शेष 244 कनालों को वादी और प्रतिवादियों के बीच वितरित किया गया था। वादी को आवंटित क्षेत्र 102 कनाल 10 मरला था जबकि 181 कनाल 10 मरला कथित रूप से प्रतिवादियों के कब्जे में थे। वादी-अपीलकर्ताओं ने इस प्रकार दावा किया कि उन्हें पूरी संयुक्त भूमि में उनके आधे हिस्से के अनुसार उनके देय से कम भूमि का 39 कनाल 10 मरला आवंटित किया गया था। 39 कनाल 10 मरला का यह क्षेत्र क्षेत्र के अंतर का आधा था।जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी-अपीलार्थियों और प्रतिवादी-प्रत्यर्थियों को आबंटित। जिला न्यायाधीश के समक्ष, तथापि, यह स्पष्ट किया गया था कि 62 कनाल 8 मरला भूमि, जिसे संयुक्त रखा गया था और विभाजित नहीं किया गया था, 286 कनाल 8 मरला के संपूर्ण स्वामित्व में से थी और शेष 224 कनाल भूमि में से, वादी अपने आधे हिस्से के कारण 112 कनाल के आवंटन के हकदार थे, लेकिन हे को

केवल 102 कनाल 10 मरला आवंटित किए गए थे जबकि प्रतिवादियों को 121 कनाल 10 मरला आवंटित किए गए थे। इस प्रकार वादी केवल संयुक्त स्वामित्व के बदले में उन्हें आवंटित क्षेत्र से बाहर प्रतिवादियों से 9 कनाल 10 मरला के क्षेत्र की वसूली करने के हकदार थे और वे आगे 62 कनाल 8 मरला में से आधे क्षेत्र के हकदार थे जो संयुक्त छोड़ दिया गया था।

(3) प्रतिवादी-प्रत्यर्थी द्वारा यह अभिवचन किया गया था कि मामला विचारणीय नहीं था और वादी-अपीलार्थी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी डिक्री के हकदार नहीं थे कि 1905 में वादी के पूर्ववर्तियों द्वारा प्राप्त डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 35 (2) में विहित न्यायालय के माध्यम से कभी भी निष्पादित नहीं किया गया था। वह डिक्री अप्रवर्तनीय हो जाने के कारण, उस डिक्री के तहत वादी-अपीलार्थियों द्वारा भूमि के कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता है। विद्वत निचली अदालतों ने उस तर्क को पूरी तरह से भूलकर स्वीकार कर लिया है कि वादी-अपीलकर्ताओं ने उस डिक्री के तहत भूमि के कब्जे का दावा कभी नहीं किया था। वाद-पत्र में उनके आरोप थे कि उन्होंने जितना उन्हें आदेश दिया गया था, उससे अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया था और उस भूमि के कब्जे में तब तक रहे जब तक कि वे 1958 में समेकन कार्यवाही में इससे वंचित नहीं हो गए, जब संपत्ति को पुनर्विभाजन योजना के अनुसार पक्षों को सौंप दिया गया। प्रतिवादियों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वादी ने 1905 की डिक्री के तहत अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया था, और इसलिए, हमारी राय में, उस डिक्री को संतुष्ट माना जाना चाहिए। वर्तमान वाद के लिए कार्रवाई का कारण 1905 की डिक्री नहीं है, बल्कि समेकन कार्यवाही में वादी को कम क्षेत्र का आवंटन है, जिसके वे हकदार थे और दावा यह है कि उनके क्षेत्र में कमी को दूर किया जाना चाहिए। 1905 में प्राप्त डिक्री का संदर्भ उनके इस दावे के समर्थन में दिया गया है कि वे... समेकन कार्यवाही में दिलसुख द्वारा छोड़े गए क्षेत्र के आधे हिस्से के हकदार थे, न कि जामबंधु हसब रसद खेवट में प्रवेश के अनुसार। यह सच है कि 1905 की डिक्री समय के साथ अप्रवर्तनीय हो गई जिसका केवल यह अर्थ है कि यदि निष्पादन के लिए कोई आवेदन किया गया होता तो निष्पादन न्यायालय उस डिक्री के अनुसार कब्जा प्राप्त करने में डिक्री-धारकों को कोई सहायता प्रदान नहीं करता, लेकिन यह उस डिक्री को मिटाता नहीं है जो वैध रूप से पारित की गई थी। उस डिक्री में निर्धारित बिंदुओं में से एक वर्तमान वादी-अपीलार्थियों के पूर्ववर्तियों और प्रतिवादियों के पूर्ववर्तियों के साथ-साथ प्रतिवादी नं। 4 जो व्यक्तिगत रूप से उस सूट का एक पक्ष था। दिलसुख द्वारा छोड़ी गई भूमि में वादी और प्रतिवादियों के संबंधित शेयरों के संबंध में निष्कर्ष अभी भी पक्षों के लिए बाध्यकारी है और वादी यह दावा कर सकते हैं कि वे फैसले में दिए गए निष्कर्ष के आधार पर दिलसुख द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के आधे हिस्से के हकदार हैं, जिसके आधार पर 1905 की डिक्री आधारित थी। इस दृष्टिकोण में हमारा समर्थन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाल्श द्वारा मुसम्मत लखरानी कौर बनाम धनराज सिंह और अन्य (1) मामले में किए गए निर्णय द्वारा किया जाता है, जिसे इस बिंदु पर लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसका निर्णय धनराज सिंह और अन्य बनाम लखरानी कौर के रूप में रिपोर्ट किया गया है। (2). उस मामले के तथ्य यह थे कि लखरानी कौर ने 1907 में प्रतिवादी के खिलाफ भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था जो नवंबर, 1907 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। उनके पति की 1904 में मृत्यु हो गई थी और प्रतिवादियों द्वारा दिया गया बचाव यह था कि भूमि उन्हें लखरानी कौर के पति द्वारा मौखिक रूप से दी गई थी। यह बचाव विफल रहा। उन्होंने 26 फरवरी, 1914 को इस आधार पर भूमि पर कब्जा करने के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया कि उन्होंने 1908 में भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था और प्रतिवादी द्वारा फिर से बेदखल कर दिया गया था। 1908 में लखरानी कौर द्वारा कथित रूप से लिया गया कब्जा अदालत के माध्यम से निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से नहीं था और प्रतिवादी ने दलील दी कि चूंकि 1907 में उसके पक्ष में पारित डिक्री अप्रवर्तनीय हो गई थी, इसलिए वह

कब्जा के लिए दूसरा मुकदमा बनाए रखने की हकदार नहीं थी और इस बात से भी इनकार किया गया था कि उसने वास्तव में 1908 में भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया था। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य का उल्लेख किया और लखरानी कौर के गवाह पर विश्वास किया जिसने कहा कि उसने वास्तव में 1908 में भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया था और प्रतिवादी पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उसने कभी भी भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया था। इन तथ्यों पर, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि श्रीमती द्वारा कब्जा प्राप्त करना। 1908 में लखरानी कौर ने डिक्री को संतुष्ट किया और बाद में जब प्रतिवादी ने कब्जा फिर से ले लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई का एक नया कारण सामने आया। अपील में, विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अवलोकन के साथ उस निर्णय का समर्थन कियाः-

"हम साक्ष्य पर पाते हैं कि वादी डिक्री के बाद कब्जे में आया था। तथ्य के इस निष्कर्ष पर हमें ऐसा लगता है कि वादी के पास कार्रवाई का कारण था, चाहे पिछली डिक्री कुछ भी हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछली डिक्री उनके शीर्षक का हिस्सा होगी। हमें नहीं लगता कि केवल यह तथ्य कि उन्होंने 1907 में अधिकार के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, उन्हें फिर से अधिकार के लिए मुकदमा करने से रोक देगा यदि उनके अधिकार में फिर से हस्तक्षेप किया गया था, और न ही हमें लगता है कि विलय का सिद्धांत निष्कासन के आदेशों पर लागू होता है।"

तर्क की समानता पर, हम तत्काल मामले में यह मानते हैं कि जब वादी के पूर्ववर्तियों ने 1905 में उनके पक्ष में घोषित की गई भूमि से अधिक भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था, तो उस डिक्री का समाधान हो गया था और जब उन्हें अब 1958 में उस भूमि के एक हिस्से से बेदखल कर दिया गया था, तो वादी के लिए कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न हुआ, जिसके आधार पर वे मुकदमा दायर करने के हकदार थे जो उन्होंने किया था।

(4) प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है जो, हालांकि, समान तथ्यों पर नहीं हैं और इसलिए, बिंदु में नहीं हैं। विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया पहला मामला खुबराम और राम धन बनाम सूरत और अन्य मामलों में पंजाब मुख्य न्यायालय का एक खंड पीठ का फैसला है। (3). उस मामले में तथ्य यह थे कि वादी ने प्रतिवादियों के विरुद्ध 29 जून, 1903 को 41 बीघा 17 बिस्वास भूमि के कब्जे के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी और 31 जुलाई, 1903 को एक दाखिलनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें डिक्री के संदर्भ में भूमि का कब्जा दिया गया था। 1 जुलाई, 1911 को उन्होंने एक और मुकदमा दायर किया, जिसमें से अपील की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मुकदमे में भूमि के कब्जे में रखे जाने के लगभग दो महीने बाद, प्रतिवादियों ने उन्हें जबरन बेदखल कर दिया था और मांग के बावजूद भूमि को सौंपने से इनकार कर दिया था। वादियों के कब्ज़े और बेदखल करने के इस आरोप को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादियों को उसी कार्रवाई के कारण कब्ज़े के लिए दूसरा मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था, जिस पर 1903 में पिछला मुकदमा दायर किया गया था। विद्वान न्यायाधीशों ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भले ही वादी ने 1903 में उनके पक्ष में पारित डिक्री के अनुसरण में कब्जा प्राप्त नहीं किया था, वे बंधक के रूप में कब्जे के लिए दूसरा मुकदमा दायर करने के हकदार थे क्योंकि बंधक अभी भी मौजूद था। हम उस बिंदु से चिंतित नहीं हैं। इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गयाः -

"जब कानून कब्जे के वितरण के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो उसके लिए विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक है, तो उस प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इससे किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए प्रक्रिया का पालन करने में किसी भी तरह की चूक को सामग्री माना जाना चाहिए।"

यह उक्ति लागू होती यदि वादी ने उस डिक्री के अनुसरण में भूमि पर कब्जा करने की मांग की होती या उस डिक्री के आधार पर मुकदमा दायर किया होता। डिवीजन बेंच के इस कथन के बाद मोती सागर, जे., निधि राम बनाम परसा राम (4) में दूसरे मामले में उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था। उस मामले में, 1910 में ऊधो राम प्रतिवादी के खिलाफ नंदन वादी के पक्ष में प्रतिवादी की भूमि पर उगने वाले आम के पेड़ों की एक निश्चित संख्या के कब्जे के लिए एक डिक्री पारित की गई थी। दूसरा मुकदमा 2 अक्टूबर, 1922 को उन्हीं पेड़ों के कब्जे के लिए दायर किया गया था। इस वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दूसरा वाद विचारणीय नहीं था क्योंकि 1910 में प्राप्त डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 35 के अनुसार कभी निष्पादित नहीं किया गया था। आरोप यह था कि डिक्री-धारक ने अपनी डिक्री के निष्पादन में अक्टूबर, 1910 में प्रतीकात्मक अधिकार प्राप्त किया था, लेकिन यह पाया गया कि वादी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई प्रतीकात्मक अधिकार नहीं दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1910 में प्रतीकात्मक अधिकार प्राप्त करने के आरोप पर विश्वास नहीं किया गया था या इसे कानून के अनुसार नहीं माना गया था। इस मामले के तथ्य भी वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं।

प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया अगला मामला हरनाम सिंह बनाम गंडा सिंह और अन्य (5) में लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय है और पीठ का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीश वही थे जिन्होंने खुब राम और राम धन के मामले का फैसला किया (3) (supra). रिपोर्ट किए गए फैसले से तथ्य स्पष्ट नहीं हैं और इसलिए हमने उस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का उल्लेख किया है, जिसे हरनाम सिंह बनाम मिलखी राम और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है। (6). उस फैसले से तथ्य भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जो प्रतीत होता है वह यह है कि तीन खसरा संख्या में भूमि के कब्जे के लिए एक डिक्री थी। निष्पादन कार्यवाही की गई और दो खसरा नंबरों के प्रतीकात्मक कब्जे को गिरदावार कानूनगो द्वारा दिया गया जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 35 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। दूसरा मुकदमा पहले से दिए गए प्रतीकात्मक कब्जे के आधार पर वास्तविक कब्जे के लिए दायर किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि आदेश 21, नियम 35 का पर्याप्त अनुपालन किया गया था, क्योंकि प्रतीकात्मक कब्जे की कार्यवाही सुबा राम की जानकारी में थी, जिनके पास दो खसरा नंबर थे और इस प्रकार उन्हें कार्यवाही की सूचना मिली थी और इसलिए, उन दो खसरा नंबरों के लिए उनके खिलाफ मुकदमा समय के भीतर माना गया था। तीसरी खसरा संख्या के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिस व्यक्ति के कब्जे में भूमि थी, उसे प्रतीकात्मक कब्जे के लिए कार्यवाही की कोई सूचना नहीं थी और इसलिए, कोई प्रतीकात्मक कब्जा नहीं दिया गया था और दूसरे मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। एकल न्यायाधीश के उस फैसले के खिलाफ एक पत्र पेटेंट अपील दायर की गई थी, जिसका निर्णय डिवीजन बेंच द्वारा किया गया था और फैसले का परिचालन भाग इस प्रकार हैः-"हमारा ध्यान उन अधिकारियों की ओर आकर्षित किया गया है जो इस नियम को निर्धारित करते हैं कि एक ऐसे मामले में दिया गया प्रतीकात्मक कब्जा जिसमें वास्तविक कब्जे की डिलीवरी के लिए दी गई डिक्री निर्णय-देनदार के खिलाफ वास्तविक कब्जे के रूप में संचालित होती है, लेकिन तीसरे व्यक्ति के खिलाफ नहीं, जो डिक्री के पक्षकार नहीं थे। इस मुद्दे पर न्यायिक राय में काफी भिन्नता है, लेकिन इस पर विस्तार करना

अनावश्यक है, क्योंकि वर्तमान मामले में डिक्री में वास्तविक कब्जे के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक कब्जे के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतीकात्मक अधिकार कानून द्वारा आवश्यक रूप से वितरित नहीं किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सीमा उस तारीख से नहीं चलती थी जिस दिन वादी के पूर्ववर्ती द्वारा डिक्री को निष्पादित किया गया था। तदनुसार मैं यह मानता हूं कि मुकदमा सीमितता से वर्जित था और अपील को खारिज कर देता हूं।

उस मामले के तथ्यों में वर्तमान मामले के तथ्यों से बहुत अधिक समानता भी नहीं है।

(6) भगत राम और अन्य बनाम अली बख्श और अन्य में लाहौर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया है। (7). उस मामले में गिरवी रखने वाले हवेली राम ने 9 अप्रैल, 1919 को आधी भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, जो गिरवी रखने का विषय था। अपील में, भूमि के क्षेत्र के संबंध में डिक्री को थोड़ा संशोधित किया गया था। पारित डिक्री संयुक्त कब्जे के लिए थी और कब्जे को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 35 (2) के प्रावधानों के तहत वितरित करने का आदेश दिया गया था। जिस दस्तावेज़ के द्वारा कब्जा दिए जाने का आरोप लगाया गया था, वह 27 जून, 1921 की एक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि बहावल बख्श, लम्बरदार और डिक्री धारक हवेली राम की उपस्थिति में अली बख्श चप्रस्सी के माध्यम से भूमि का कब्जा दिया गया था। डिक्री-धारक द्वारा कब्जे की एक औपचारिक रसीद भी 28 जून, 1921 को निष्पादित की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यह कब्जा पटवारियों और अन्य गवाहों की उपस्थिति में भूमि की जुताई करके प्राप्त किया गया था। 26 जून, 1933 को वादी, जो हवेली राम के वंशज थे, ने इस आरोप पर उसी भूमि पर कब्जा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि उन्हें पिछले पांच या छह वर्षों के भीतर बेदखल कर दिया गया था। अपने वाद को सीमा के भीतर लाने के लिए, वादी ने 27 जून, 1921 के दखलनमा पर भरोसा किया, यानी उस दस्तावेज़ पर, जिसमें ऊपर उल्लिखित पटवारियों की रिपोर्ट है। इन तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया थाः-"इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि 29 जनवरी, 1920 की अंतिम डिक्री संयुक्त कब्ज़े के लिए थी और ऐसा कब्ज़ा केवल आदेश 21, नियम 35 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता में विधायिका द्वारा निर्धारित विशेष तरीके से दिया जा सकता है। यह किसी अन्य तरीके से संयुक्त कब्जा देने का प्रयास करने के लिए किसी की क्षमता के भीतर नहीं है, और यदि पटवारियों या किसी अन्य व्यक्ति ने विधायिका की स्पष्ट भाषा के विपरीत तरीके से इस तरह के संयुक्त कब्जे को देने के लिए खुद को लिया, तो उनकी कार्रवाई का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा।

तत्काल मामले में ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है और इसलिए, यह निर्णय भी प्रासंगिक नहीं है।

(7) भैरों राय और अन्य बनाम सरन राय (8) और हनुमान प्रसाद नारायण सिंह बनाम मथुरा प्रसाद नारायण सिंह (9) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो पूर्ण पीठ निर्णय इस बिंदु से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं और इसलिए सहायक नहीं हैं।

(8) प्रत्यर्थी के विद्वत वकील द्वारा जिस अंतिम मामले पर भरोसा किया गया है, वह श्री रामेश्री बनाम श्री वैष्णो दिट्टी (10) है, जिसमें केवल यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 35 (2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति पर वारंट चिपकाकर और ड्रम बजाकर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो कानूनी रूप से कोई सुपुर्दगी नहीं होती है और कब्जे के लिए डिक्री निष्पादित किए बिना, डिक्री-धारक निर्णय-देनदारों के साथ शेयरधारक नहीं बन सकता है और

परिणामस्वरूप संपत्ति के लाभ में हिस्सेदारी नहीं मांग सकता है। तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और इस फैसले से कोई मदद नहीं ली जा सकती है।

(9) शुद्ध परिणाम यह है कि केवल दो इलाहाबाद निर्णय, मुसम्मत लखरानी कौर बनाम धनराज सिंह और अन्य (1) और धनराज सिंह और अन्य बनाम लखरानी कौर (2) (उपर्युक्त), हमारे सामने मुद्दे को तय करने में सहायक हैं। हम विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों से इस आशय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि डिक्री के पारित होने के बाद उसके अनुसार कब्जा प्राप्त करना कब्जे के लिए डिक्री की संतुष्टि के बराबर है और यदि डिक्री धारक को उसके बाद बेदखल कर दिया जाता है, तो उसे उसके बेदखल होने के आधार पर दूसरा मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण मिलता है, बशर्ते कि उसके बेदखल होने की तारीख से सीमा के भीतर एक मुकदमा दायर किया जाए। वादी के शीर्षक के समर्थन में पहले वाले पर भरोसा किया जा सकता है।

(10) प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया एकमात्र अन्य बिंदु यह है कि वादी-अपीलार्थियों द्वारा जिस भूमि का कब्जा मांगा गया है, उसे वाद में विवरण के साथ नहीं कहा गया है। शिकायत के संदर्भ में, हम पाते हैं कि 224 बीघा 5 बिस्वास के अनुरूप भूमि का विवरण मूल रूप से दिलसुख और श्रीमती से संबंधित है। जिवानी, जिसके संबंध में डिक्री 1905 में पारित की गई थी, वाद के पैरा 6 में दी गई है, जैसा कि वर्ष 1945-46 के लिए जामबंदी में अभिलिखित है। पुनर्विभाजन की कार्यवाही में उस संयुक्त स्वामित्व के अपने हिस्से के कारण प्रतिवादियों को आवंटित किला नंबरों का उल्लेख वाद के पैरा 7 में किया गया है, जबकि संयुक्त रूप से रखी गई 62 कनाल 8 मरला की भूमि का वर्णन वाद के पैरा 8 में किला नंबरों द्वारा किया गया है। प्रत्येक प्रतिवादी के कब्जे वाली भूमि का उल्लेख वाद के पैरा 10 में किया गया है। चीजों की प्रकृति में, वादी-अपीलकर्ता 39 कनाल 10 मरला भूमि का विनिर्देशन नहीं कर सके, जिस पर उन्होंने वाद में अपना दावा किया था। यह क्षेत्र अब केवल 9 कनाल 10 मरला पाया गया है। संयुक्त रखी गई भूमि का शिकायत के पैरा 8 में अलग से वर्णन किया गया है। अतः वादी-अपीलार्थियों के वाद को 9 कनाल 10 मरला की सीमा तक वाद के पैरा 7 में वर्णित भूमि के कब्ज़े के लिए और वाद के पैरा 8 में वर्णित 62 कनाल 8 मरला की भूमि के संयुक्त कब्ज़े के लिए आदेश देने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वे दिलसुख और श्रीमती द्वारा छोड़ी गई भूमि के आधे हिस्से के हकदार पाए गए हैं। जिवानी।

(11) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, यह अपील स्वीकार की जाती है और वादी-अपीलार्थियों के मुकदमे को पूरे खर्च के साथ ऊपर के रूप में तय किया जाता है।

मेहर सिंह, सी. जे. -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा**)